प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर–अजमेर
दिनांकः 12.06.2025 समय : 09:00 ए.एम.

- प्रदेश में प्रचण्ड गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोडे –श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48 डिग्री सैल्सियस पर पंहुचा।
- गिव–अप अभियान के तहत राज्य मे अब तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी।
- प्रदेश में अज्ञात, बेसहारा और मानसिक रूप से अक्षम रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
- विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर आज बच्चों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे।

00000

प्रदेश में प्रचण्ड गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड दिए हैं। श्री गंगानगर में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 7 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री सैल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार फलौदी और चूरू में 45 दशमलव 8, चित्तौडगढ में 45 दशमलव 7, वनस्थली और दौसा में 45 दशमलव 2, कोटा और बीकानेर में 45 दशमलव 1 डिग्री सैल्सियस तापमान मापा गया। राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 44 दशमलव 4 डिग्री सैल्सियस रहा। भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पडा है। लोग दिन के समय घरों में ही रहने पर मजबूर है। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि वहां तेज गर्मी से हाल बेहाल है। न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी लू जैसे हालात बने हुए है।

0000

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तम्भ साबित हो रहा है। समिट ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है, जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। वे कल मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियेां के साथ एमओयू की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास को समर्पित निवेश और उद्योग संबंधी नीतियों से समिट के तहत हुए एमओयू लगातार धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ अगले महीने में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलक्टर को लैंड बैंक से संबंधित रेकार्ड की रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।

0000

प्रदेश में पिछले वर्ष शुरू किए गए गिव–अप अभियान के तहत अभी तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल कोटा में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सक्षम लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। श्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल के दोबारा शुरू होने के बाद 37 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोदारा ने अपात्र लोगों से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की अपील की।

0000

देश में कृषि को और आधुनिक तथा वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किये गये विकसित कृषि संकल्प अभियान का आज आखिरी दिन है। 29 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत देशभर में विभिन्न स्थानों पर कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे है। प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित कर खरीफ फसलों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। इसी कडी में कल झुंझुनूं की काजड़ा ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा गया। इसमें कृषि विशेषज्ञ राजेंद्र नागर ने कृषि और उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। भगीना और फरट ग्राम पंचायतों के किसान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सलूम्बर के लसाडिया

तहसील में आयोजित कार्यक्रम में 200 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को मक्का की उत्पादकता बढाने और मुर्गीपालन तथा बकरी पालन जैसे वैकल्पिक आय स्त्रोत अपनाने की सलाह दी गई।

0000

भीलवाडा जिले में साढे तीन लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ पंहुच रहा है। विशेष तौर पर इससे छोटे किसानों की खाद बीज खरीदने सहित विभिन्न परेशानियों का समाधान हो रहा हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि केन्द्र सरकार की ये योजना किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

000

प्रदेश में अज्ञात, बेसहारा और मानसिक रूप से अक्षम रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी। इन रोगियों को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक संयुक्त एमओयू किया है। इसके तहत रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट या एनजीओ के माध्यम से अस्पतालों में लाए जाने वाले रोगियों के निःशुल्क ईलाज की व्यवस्था की जायेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पाये गये बेसहारा रोगियों को पहचान पत्र के अभाव में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या अन्य योजनाओं के तहत ईलाज की सुविधा नहीं मिल पाती थी।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐसे रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ऐसे रोगियों के समुचित उपचार के लिए दिशा—निर्देश जारी किए हैं।

000

आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए इस साल पहली जुलाई से आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। रेलवे ने यह कदम तत्काल टिकटों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। नई योजना के अनुसार, 15 जुलाई से कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा। थोक बुकिंग को रोकने के लिए, टिकटिंग एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान ओपनिंग—डे तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। एसी क्लास के लिए यह प्रतिबंध सुबह 10 से साढ़े दस बजे तक और नॉन—एसी क्लास के लिए सुबह 11 से साढ़े ग्यारह बजे तक रहेगा।

00000

आज विश्व बालश्रम निषेध दिवस है। बच्चों का शोषण रोकने और बालश्रम को समाप्त करने के लिए इस वर्ष प्रयासों को तेज़ करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से कल जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में लगभग तेरह करोड़ अस्सी लाख बाल श्रमिक थे। इनमें से लगभग पांच करोड़ चालीस लाख बच्चे ऐसे खतरनाक कामों में लगे हुए थे जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के प्रतिकूल है। बालश्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। करौली में आज से बालश्रम मुक्त करौली अभियान की शुरूआत की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन के इस नवाचार के माध्यम से 11 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

....

00000